



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]
No. 60]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 19, 2003/चैत्र 29, 1925
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 19, 2003/CHAITRA 29, 1925

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2003

सं. टीएएमपी/92/2002-वी.पी.टी.—महापत्रन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण, विशाखापट्टनम के आयातकों तथा निर्यातकों के लिए परिमाण छूट योजना शुरू करने संबंधी विशाखापट्टनम पत्रन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार अनुमोदित करता है।

महापत्रन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/92/2002-वी.पी.टी.

विशाखापट्टनम पत्रन न्यास आवेदक

आदेश

(17 मार्च, 2003 को पारित)

यह मामला विशाखापट्टनम के आयातकों तथा निर्यातकों के लिए परिमाण छूट योजना शुरू करने संबंधी विशाखापट्टनम पत्रन न्यास (वी.पी.टी.) से प्राप्त प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें रखी हैं :—

2. वी.पी.टी. ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में निम्नलिखित बातें रखी हैं :—

- (i) आयातक/निर्यातक द्वारा पिछले वर्ष हैंडल किए गए यातायात को परिमाण छूट योजना के लिए आधार माना जाएगा।
- (ii) प्रस्तावित परिमाण छूट योजना उसी आयातक/निर्यातक के लिए लागू होगी जिसने पिछले वर्ष के दौरान 50,000 टन कार्रो हैंडल किया हो।
- (iii) संबंधित आयातक/निर्यातक के पिछले वर्ष के शूपुट से चालू वर्ष में 110% से ऊपर होने पर प्रस्तावित परिमाण छूट योजना लागू होगी।
- (iv) वी.पी.टी. ने निम्नलिखित परिमाण छूट योजना का अनुमोदन प्राप्त किया है :—

विवरण	प्रस्तावित परिमाण छूट
पिछले वर्ष के शूपुट से 110%	कोई छूट नहीं
110% से 120% तक	पिछले वर्ष से 110% अधिक मात्रा से अधिक होने पर घाट शुल्क में 10% की छूट।
120% से 130% तक	पिछले वर्ष से 120% मात्रा से अधिक होने पर घाट शुल्क में 15% की छूट।
130% तथा अधिक	पिछले वर्ष से 130% मात्रा से अधिक होने पर घाट शुल्क में 20% की छूट।

3.1 प्रस्ताव की एक प्रति टिप्पणियों के लिए विभिन्न संबंधित प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों को भेजी गई थी। विभिन्न प्रयोक्ताओं/पत्तन प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधि निकायों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में वि.पी.टी. को भेज दिया गया था।

3.2. इस मामले के संबंध में एक संयुक्त सुनवाई वि.पी.टी. परिसर में 21 जनवरी, 2003 को आयोजित की गई। संयुक्त सुनवाई के वि.पी.टी. तथा पत्तन प्रयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए।

3.3. जैसा कि संयुक्त सुनवाई में निर्णय लिया गया है कि वि.पी.टी. ने बाद में अपने प्रस्ताव में वित्तीय कठिनाई को दिखाते हुए एक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वि.पी.टी. ने पात्रता मानदण्ड भी संशोधित कर दिए हैं। वि.पी.टी. ने अपने संशोधित प्रस्ताव में निम्नलिखित बिन्दु रखे हैं :—

- (i) प्रस्तावित परिणाम छूट योजना तभा लागू होगी जब किसी आयातक/निर्यातक ने पिछले वर्ष के दौरान 50,000 टन शुल्क कारगो तथा 10,000 टन द्रव कारगो का प्रहस्तन किया हो।
- (ii) पिछले दो वर्षों के दौरान किसी आयातक/निर्यातक द्वारा प्राप्त कारगो-वार औसत श्रूपुट को बेंचमार्क माना जाएगा। यदि किसी आयातक/निर्यातक ने केवल वर्ष 2002-03 में कारगो का प्रदूस्तन किया है तो वर्ष 2002-03 के दौरान प्रदूस्तन किए गए श्रूपुट को परिणाम छूट योजना हेतु बेंचमार्क माना जाएगा।
- (iii) इस प्रकार प्राप्त बेंचमार्क 2 वर्ष के लिए स्थिर रहेगा तथा कम से कम 2 वर्ष के औसत को ध्यान में रखकर ही संशोधित किया जाएगा।
- (iv) वर्ष 2003-04 में आए नए आयातक/निर्यातक परिणाम छूट योजना के लिए वर्ष 2005-06 में पात्र होंगे।
- (v) योजना 1 अप्रैल, 2003 से लागू होगी तथा वर्ष अर्थात् 2001-02 और 2002-03 का औसत निष्पादन बेंचमार्क होगा।
- (vi) प्रस्तावित परिमाण छूट प्रस्ताव के अनुसार ही बनी हुई है।

3.4. वि.पी.टी. ने उल्लेख किया है कि छूट केवल घाट शुल्क तत्व पर लौह अयस्क के लिए ₹. 26.20 प्रति मैट्रिक टन दी जाएगी तथा टिप्पिंग तथा ढुलाई प्रभारों पर कोई छूट नहीं होगी।

3.5. प्रत्येक आयातक, निर्यातक को प्राप्त होने वाले लाभ को वि.पी.टी. ने तैयार किया है जो पिछले दो वर्ष अर्थात् 2000-01 तथा 2001-02 के दौरान आयातक, निर्यातक के औसत निष्पादन पर आधारित है। यदि प्रस्तावित परिमाण छूट योजना लागू हो गई होती तो वर्ष 2002-03 में वित्तीय विवक्षा ₹. 1.38 करोड़ होती।

3.6. इस मामले में विचार-विमर्श संबंधी कार्यवाहियाँ इस प्राधिकरण के कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों तथा संबंधित पार्टीयों द्वारा किए गए तर्कों को संबंधित पार्टीयों के पास अलग से भेजे जाएंगे। ये ब्यौरे हमरी वेबसाईट (www.tamp.nic.in) पर भी उपलब्ध होंगे।

5. इस मामले की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संबंध में निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :—

- (i) वर्तमान उपयोक्ताओं के परिणाम को वि.पी.टी. के माध्यम से सुधार के लिए कम से कम शुरू में तो वि.पी.टी. के प्रस्ताव पर प्रशुल्क प्रोत्साहन योजना, जिसका लक्ष्य उक्त उपयोक्ता थे, से अधिक विचार किया जाए।
- (ii) उपयोक्ताओं द्वारा दिए गए सुझाओं में से कुछ सुझाओं को समायोजित करने के लिए वि.पी.टी. ने बाद में अपनी योजना को आशोधित किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि छूट आयातक/निर्यातक आधार पर अनुमत होगी बशर्ते कि वह निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। निर्धारित सीमा को पिछले दो वर्ष का श्रूपुट लेकर थोड़ा उदार बनाया गया है। वि.पी.टी. ने भी 10,000 टन का अलग आधार नियत करके लिकिवड बल्कि कारगो उपयोक्ताओं की मांग मान ली है।
- (iii) प्रस्ताव से उपयोक्ताओं को उनके द्वारा लाए गए अतिरिक्त श्रूपुट पर कुछ राहत मिलती है। स्पष्टता वि.पी.टी. के प्रस्ताव को किसी तिमाही (क्वार्टर) से कोई गंभीर आपत्ति नहीं हो सकती है। फिर भी पात्रता सीमा, निर्धारित सीमा तथा छूट सीमा पर बहुत सुशाश्वत हैं। इस बात को माना जाए कि वि.पी.टी. का प्रयोग प्रयोगात्मक है और योजना की प्रभावोत्पादकता केवल बाद में ही आंकी जा सकती है। प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना बाद में अनुकूल हो सकती है। योजना के विभिन्न मानकों के लिए उपलब्ध मजबूत वैज्ञानिक आधार के अभाव में यह तर्कसंगत है कि प्रस्तावित योजना को बिना किसी आशोधन के प्रायोगिक आधार पर परिचालित किया जा सकता है। तथापि वि.पी.टी. वित्त वर्ष 2003-04 के अंत में योजना की समीक्षा कर सकता है और आवश्यक होने पर योजना में आशोधनों के लिए प्रस्ताव रख सकता है।
- (iv) वि.पी.टी. ने वर्ष 2002-03 में परिमाण छूट के कारण ₹. 1.38 करोड़ की नोशनल वित्तीय विवक्षा दर्शायी है। वर्ष 2003-04 में वर्तमान वृद्धि प्रवृत्ति चालू रहने पर 2003-04 में समान वित्तीय विवक्षा हो सकती है। असल में इसे पत्तन का राजस्व घाटा नहीं कहा जा सकता क्योंकि छूट केवल अतिरिक्त श्रूपुट पर ही होगी। इसके अलावा यदि कारगो का अतिरिक्त श्रूपुट प्राप्त होता है तो अन्य संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व जो काफी हद तक घाट शुल्क में छूट दिए जाने के कारण राजस्व में कटौती को ऑफ-सेट कर सकता है।

(v) जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह प्रस्ताव मूल रूप से वर्तमान प्रयोक्ताओं के लिए लाभदायी है। भविष्य में पत्तन के यातायात को बढ़ाने के लिए यह नए कारगों को आकर्षित करने में बेहतर अभिगम हो सकता है। जैसा कि आई.एन.एस.ए. ने उल्लेख किया है कि वी.पी.टी. के लिए यही उचित होगा कि वह नए कारगों यातायात को प्रेरित करने हेतु प्रशुल्क उपाय करे। वी.पी.टी. को सलाह दी जाती है कि वह वर्ष 2003-04 के अंत में प्रस्तावित योजना की समीक्षा करते समय इस बात पर विचार करे।

5. परिणाम स्वरूप तथा समग्र विचार विमर्श के पश्चात् यह प्राधिकरण वी.पी.टी. पर 1 अप्रैल, 2003 से निम्नलिखित परिमाण छूट योजना को अनुमोदित करता है :—

(क) पात्रता मानदण्ड

- वह आयातक/निर्यातक, जिसने पिछले वित्त वर्ष में न्यूनतम शुष्क कारगो 50,000 टन तथा द्रव कारगो 10,000 टन का प्रहस्तन किया हो, परिमाण छूट योजना का पात्र होगा।
- आयातक/निर्यातक का पिछले दो वर्ष का कारगो वार औसत शूपुट बेंच मार्क होगा। जिन आयातकों/निर्यातकों ने केवल वर्ष 2002-03 में कारगो हैंडल किया है उनके लिए वर्ष 2002-03 में प्राप्त शूपुट बेंच मार्क होगा।
- वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 का औसत शूपुट वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 का बेंच मार्क बनेगा। तत्पश्चात् पिछले दो वर्ष के औसत को ध्यान में रखकर बेंच मार्क संशोधित किया जाएगा।
- घाट शुल्क में छूट निम्नानुसार अनुमत होगी :—

क्रम. सं.	शूपुट विस्तार	घाट शुल्क पर छूट
(क)	संपूर्ण तथा बेंच मार्क का 110% शामिल करते हुए	शून्य
(ख)	110% से ऊपर तथा बेंच मार्क के 120% तक	10%
(ग)	120% से ऊपर तथा बेंच मार्क के 130% तक	15%
(घ)	बेंच मार्क के 130% ऊपर	20%

नोट : लौह अयस्क के संबंध में छूट केवल घाट शुल्क तत्व पर रुपए 26.20 प्रति मैट्रिक टन अनुमत होगी।

अ. ल. बोगिरवार, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/2003/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2003

No. TAMP/92/2002-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal from the Visakhapatnam Port Trust to introduce volume discount scheme to the importers and exporters of the Visakhapatnam port as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/92/2002 - VPT

The Visakhapatnam Port Trust

....

Applicant

ORDER

(Passed on this 17th day of March 2003)

This case relates to a proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) to introduce volume discount scheme to the importers and exporters of the Visakhapatnam port.

2. The VPT has made the following points in its proposal:

- (i). The basis for volume discount scheme will be taken as previous year traffic handled by an importer/exporter.
- (ii). The proposed volume discount scheme will be applicable to importer/exporter who had handled at least 50,000 tonnes of cargo during the previous year.
- (iii). If the throughput of the respective importer/exporter during the current year is beyond 110% of the throughput of previous year then only the proposed volume discount scheme will be applicable.
- (iv). The VPT has sought approval to the following volume discount scheme:

Description	Volume discount proposed
Upto 110 % of the previous year's throughput	No Discount
110% to 120%	10 % discount in Wharfage over and above the quantity of 110% over previous year
120% to 130%	15 % discount in Wharfage over and above the quantity of 120% over previous year
130% and above	20 % discount in Wharfage over and above the quantity of 130% over previous year

3.1. A copy of the proposal was forwarded to various concerned users/representative bodies of port users for comments. The comments received from the various users / representative bodies of port users were forwarded to the VPT as feed back information.

3.2. A joint hearing in this case was also held on 21 January 2003 at the VPT premises. At the joint hearing, the VPT and the port users have made their submissions.

3.3. As decided at the joint hearing, the VPT has subsequently furnished an analysis bringing out the financial implication of its proposal. The VPT has also revised the eligibility criteria. The VPT has made following points in its revised proposal:

- (i). The proposed volume discount scheme will be applicable, only if an importer/exporter had handled at least 50,000 tonnes of dry cargoes or 10,000 tonnes of liquid cargoes during the previous year.
- (ii). The average cargowise throughput achieved by an importer/exporter during the preceding two years will be the benchmark. If any importer/exporter has handled cargo only in the year 2002-03, the throughput handled during 2002-03 will be considered as benchmark for volume discount scheme.

- (iii). The benchmark thus arrived will remain static for a period of two years and will be revised thereafter taking into account the average of latest two years.
- (iv). New importer/exporter in 2003-04 will become eligible for volume discount scheme only in 2005-06.
- (v). The scheme will be in force w.e.f 1 April 2003 and the benchmark will be the average performance of the two years i.e., 2001-02 and 2002-03.
- (vi). The proposed volume discount is retained as per the earlier proposal.

3.4. The VPT has pointed out that discount will be given only on wharfage element of Rs 26.20 PMT for iron ore and there will not be any discount on the tippling and haulage charges.

3.5. The benefit likely to accrue to each importer exporter has been worked out by the VPT based on the average performance of each of importer exporter during last two year i.e., 2000-01 and 2001-02. The financial implication for the year 2002-03, if the proposed volume discount scheme had been in force, works out to Rs.1.38 crores.

3.6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpts of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be available in our website (www.tamp.nic.in).

5. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i). The proposal of the VPT is to be viewed more of a tariff incentive scheme primarily aimed at the existing users, at least in the initial period, to improve their volumes through the VPT.
- (ii). The VPT has modified the scheme subsequently to accommodate some of the suggestions made by the users. It has clarified that the discount will be allowed on an importer / exporter basis, subject to fulfillment of the eligibility conditions laid down. The cut-off limit has also been slightly liberalised by taking average throughput of the last two years. The VPT has also conceded to the demand of liquid bulk cargo users by fixing a separate base of 10,000 tonnes.
- (iii). The proposal is to provide some relief to the users on the additional throughput brought by them. Obviously, there cannot be any serious objection from any quarter to the proposal of the VPT. Nevertheless, there are a lot of suggestions on the eligibility limit, the cut-off limit, the extent of discounts, etc. It is to be recognised that the attempt of the VPT is an experimental one and the efficacy of the scheme can be judged only at a later stage. Based on the experience gained, the scheme can be finetuned at a later stage. In the absence of any strong scientific basis available for the various parameters of the Scheme, it is found reasonable that the proposed scheme can be put into operation, without any modification, on an experiential basis. The VPT can, however, review the Scheme at the end of the financial year 2003-04 and come up with its proposal for modifications in the scheme, if necessary.
- (iv). The VPT has indicated a notional financial implication of Rs 1.38 crores for the year 2002-03 on account of volume discounts. Subject to the existing growth trend continuing in 2003-04, there may be a similar financial implication in the year 2003-04. Strictly speaking, this cannot be called as a revenue loss to the port as the discount will be on additional throughput only. Further, if additional throughput of cargo is achieved, there can be an increased revenue generated from the other associated activities which may to a great extent, off set the reduction in revenue due to discounts allowed on wharfage.

1139 E1/63-2

(v). As has been mentioned earlier, this proposal primarily benefits the existing users. In order to boost up the port's traffic in future, it may be a better approach to attract new cargo also. As pointed out by the INSA, it will be worthwhile for the VPT to draw up tariff measures to induce new cargo traffic. The VPT is advised to take this aspect into consideration while reviewing the proposed scheme at the end of 2003-04.

5. In the result, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following volume discount scheme at the VPT w.e.f. 1 April 2003:

"(A). Eligibility criteria

- (i). An importer / Exporter who had handled a minimum of 50000 Tonnes of dry cargo or 10000 Tonnes of liquid cargo in the immediate preceding financial year will qualify for volume discount scheme.
- (ii). The cargowise average throughput for the preceding two years of an importer/exporter will be for the benchmark. For importers/exporters who handled cargo only in 2002-03, the benchmark will be the throughput achieved by them in the year 2002-03.
- (iii). The average of throughput for 2001-02 and 2002-03 will form the benchmark for the years 2003-04 and 2004-05. Thereafter, the benchmark will be revised taking into account the average of the immediately preceding two years.
- (iv). Discount on wharfage will be allowed as follows :

S.No.	Range of throughput	Discount on wharfage
(a)	Upto and inclusive of 110% of the benchmark	Nil
(b).	Above 110% and upto 120% of the benchmark	10%
(c).	Above 120% and upto 130% of the benchmark	15%
(d).	Above 130% of the benchmark	20%

Note : In respect of iron ore, the discount will be allowed only on the wharfage element of Rs 26.20 PMT."

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[No. ADVT/III/IV/143/2003/Exty.]